[2011] 6 एस सी आर 1050

राजस्थान राज्य

बनाम

तालेवर एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 937/2005)

17 जून, 2011

[डॉ. बी.एस. चौहान और स्वतंत्र कुमार, जे.जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 114, चित्रण (ए) - हत्या के साथ डकैती के एक मामले में बरामद वस्तुओं के आधार पर अनुमान - 8 आरोपियों में से दो आरोपी-प्रतिवादियों को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया - राज्य द्वारा अपील - माना: माना जाता है कि, वहाँ अभियुक्त की पहचान का कोई सबूत नहीं है - प्रकटीकरण बयानों पर वसूली घटना की तारीख से समय के करीब नहीं थी - और अधिक, वसूली या तो नकदी, छोटी चीजें या स्कूटर की है, जो बिना किसी कठिनाई के हाथ बदल सकती है - इसलिए, धारा 114 के तहत अभियुक्तों के खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, उदाहरण (ए) - उन्हें अपराध से जोड़ने के लिए उनके प्रकटीकरण बयानों पर की गई वसूली के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है - दंड संहिता, 1860 - उपधारा 395, 396 और 397.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

दोषमुक्ति के खिलाफ अपील - माना जाता है: केवल असाधारण मामलों में, जहां बाध्यकारी परिस्थितियां होती हैं और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत दोषमुक्ति के

आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है - अपीलीय अदालत को निर्दोषता की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए अभियुक्त और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने से उसकी बेगुनाही की धारणा को बल मिलता है - जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो, वहां नियमित तरीके से हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों - मौजूदा मामले में, हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय और आदेश के साथ प्रतिवादियों को बरी करना - दंड संहिता, 1860 - उपधारा 395,396 और 397 - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136।

17/12/1996 की सुबह पीडब्लू 13 द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि पिछली रात 8-10 बदमाशों ने उनके घर में डकैती की थी जिसमें डकैतों ने उनके चौकीदार और उनके पड़ोसी नामक दो लोगों की हत्या कर दी और फरार हो गए। नकदी, आभूषण और चांदी के बर्तन। प्रतिवादी संख्या 2 को 24/12/1996 को और प्रतिवादी संख्या 1 को 19/1/1997 को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, कुछ नकदी और कुछ सामान बरामद किए गए। दोनों प्रतिवादियों सहित कुल नौ आरोपियों को मुकदमे का सामना करना पड़ा। एक अभियुक्त की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने बाकी सभी 8 आरोपियों को दोषी करार दिया. अपील पर, उच्च न्यायालय ने छह आरोपियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए, उत्तरदाताओं को बरी कर दिया।

राज्य द्वारा दायर तत्काल अपील में, न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था: क्या केवल उनके प्रकटीकरण बयानों पर की गई वसूली के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

आयोजित: 1.1. जहां तक दोनों उत्तरदाताओं/अभियुक्तों का संबंध है, स्वीकृत तथ्य यह है कि कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित ही नहीं की गई थी। इसके अलावा, किसी भी चश्मदीद गवाह, विशेष रूप से 'पीडब्लू 12', 'पीडब्लू 13', 'पीडब्लू 2', 'पीडब्लू 14' और 'पीडब्लू 15' ने अदालत में किसी भी उत्तरदाता की पहचान नहीं की। इसलिए, जहां तक उनकी पहचान का सवाल है, कोई सबूत नहीं है। [पैरा 6]

1.2. जहां तक अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर की गई वसूली के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष का संबंध है, इस मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि जहां अभियुक्तों के खिलाफ केवल सबूत चोरी की संपत्तियों की वसूली है, फिर भी परिस्थितियां संकेत दे सकती हैं चोरी और हत्या एक ही समय में की गई होगी, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि चोरी की संपत्ति रखने वाले व्यक्ति ने हत्या की है। यह बरामद की गई संपत्ति की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि क्या इसके आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की संभावना है। संदेह को सबूत की जगह नहीं लेनी चाहिए. [पैरा 7.7]

गुलाब चंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, **1995 (3) एससीआर 27 = एआईआर 1995 एससी 1598;** तुलसीराम कानू बनाम राज्य, **एआईआर 1954 एससी 1;** गीजगंदा सोमैया बनाम कर्नाटक राज्य, **2007 (3) एससीआर 899 = एआईआर 2007 एससी 1355,** सांवत खान बनाम राजस्थान राज्य, **एआईआर 1956 एससी 54;** ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य **1983 (2) एससीआर 552 = एआईआर 1983 एससी 446;** संजय@काका ईएफसी. आदि बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) **एआईआर 2001 एससी 979;** रोनी एलियास रोनाल्ड जेम्स अलवारिस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, **एआईआर 1998 एससी 1251;** बैजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य **1978 (2) एससीआर 1978= एआईआर 1978 एससी 522;** मुकुंद @ कुंडू मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य **1997 एआईआर 2622 - संदर्भित।**

1.3. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 को 24/12/1996 को गिरफ्तार किया गया था और 29/12/1996 को उसके प्रकटीकरण बयान पर एक चांदी का गिलास और एक हजार

रुपये बरामद किए जाने का आरोप लगाया गया था। पुनः प्रकटीकरण विवरण दिनांक 2/1/1997 पर, डकैती में इस्तेमाल किया गया कथित स्कूटर बरामद किया गया। इसी तरह, प्रतिवादी नंबर 1 को 19/1/1997 को गिरफ्तार किया गया था और 26/1/1997 को उसके प्रकटीकरण बयान पर, दो हजार रुपये, एक चांदी की अंगूठी और अपराध में इस्तेमाल की गई एक एम्बेसडर कार की चाबी बरामद की गई थी। . इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं/अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी के प्रकटीकरण बयान पर वसूली घटना की तारीख से समय के करीब नहीं थी। और तो और, वसूली या तो नकदी, छोटी चीज़ों या वाहनों की होती है जिन्हें बिना किसी कठिनाई के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 चित्रण (ए) के तहत दो उत्तरदाताओं/अभियुक्तों के खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उनके प्रकटीकरण बयानों पर की गई बरामदगी के आधार पर उन्हें अपराध के कमीशन से जोड़ने के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। [पैरा 8]

2. उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को बरी करने के फैसले और आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा तत्काल अपील की गई है। इस मुद्दे पर कानून इस आशय से तय है कि केवल असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी परिस्थितियां हैं और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है। अपीलीय अदालत को अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट के बरी होने से उसकी बेगुनाही की धारणा को बल मिलता है। जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो वहां नियमित तरीके से हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों। मौजूदा मामले में, प्रतिवादियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के सुविचारित फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 9-10]

ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **एआईआर 2011 एससी 280;** वी एस अच्युतानंदन बनाम आर बालकृष्ण पिल्लई और अन्य, **(2011) 3 एससीसी 317;** और रुकिया बेगम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, **(2011) 4 एससीसी 779, पर निर्भर**

केस लॉ संदर्भ:

1995 (3) एससीआर 27	**पैरा 7.1**	**को संदर्भित करता है**
2007 (3) एससीआर 899	**पैरा 7.2**	**को संदर्भित करता है**
एआईआर 1956 एससी 54	**पैरा 7.2**	**को संदर्भित करता है**
एआईआर 1954 एससी 1	**पैरा 7.3**	**को संदर्भित करता है**
1983 (2) एससीआर 552	**पैरा 7.4**	**को संदर्भित करता है**
एआईआर 2001 एससी 979	**पैरा 7.5**	**को संदर्भित करता है**
एआईआर 1998 एससी 1251	**पैरा 7.6**	**को संदर्भित करता है**
1978 (2) एससीआर 1978	**पैरा 7.6**	**को संदर्भित करता है**
1997 एआईआर 2622	**पैरा 7.6**	**को संदर्भित करता है**
एआईआर 2011 एससी 280	**पैरा 9**	**पर निर्भर करता है**
(2011) 3 एससीसी 317	**पैरा 9**	**पर निर्भर करता है**
(2011) 4 एससीसी 779	**पैरा 9**	**पर निर्भर है**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: 2005 की आपराधिक अपील संख्या 937।

2002 की डीबी आपराधिक अपील संख्या 1579 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 27/10/2004 से।

उपस्थित पक्षों के लिए मनीष सिंघवी, एएजी, मिलिंद कुमार, अल्ताफ हुसैन, हरबंस लाल बजाज।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ बी एस चौहान, जे 1. यह अपील राजस्थान राज्य द्वारा उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ द्वारा 27/10/2004 को पारित फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें 2002 की आपराधिक अपील संख्या 1579 में उत्तरदाताओं को बरी कर दिया गया था, उनकी दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया था और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक), लक्ष्मणगढ़, अलवर द्वारा दिनांक 2.11.2002 को सत्र प्रकरण संख्या 4, 2002 (14/2000) में भारतीय दंड की धारा 395, 396 और 397 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। संहिता, 1860 (इसके बाद इसे आईपीसी कहा जाएगा)।

2. इस मामले को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं:

संतोष जगवेयन (पीडब्ल्यू 13) ने 17/12/1996 को सुबह 8:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई कि 16 और 17 दिसंबर 1996 की मध्यरात्रि में शोर सुनकर उन्होंने अपने चौकीदार गोपाल नेपाली (मृतक) को भेजा। उसके घर की छत. गोपाल नेपाली ऊपर गया और छत का गेट खोला और देखा कि 8 से 10 आरोपी छत का दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तुरंत गोपाल नेपाली (मृतक) पर गोली चलाई और घर में घुस गए। आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की पत्नी शशि देवी (पीडब्लू 12), प्रीति (पीडब्लू 14) और उसकी बेटियों संध्या (पीडब्लू 15) को बाथरूम में बंद कर दिया और चल संपत्तियों को लूटना शुरू कर दिया। इसी बीच उसके पड़ोसियों ने आवाज लगायी. ऐसे में आरोपी ने तुरंत श्रीमती अनीता यादव पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. अनीता यादव (मृतक) के पति कृपा दयाल यादव (पीडब्लू 2) ने एक आरोपी को पकड़ लिया लेकिन अन्य आरोपियों ने उसे बंदूक की बट से पीटा और आरोपी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। आरोपी नकदी, आभूषण और चांदी के बर्तन आदि लेकर फरार हो गए।

बी उक्त शिकायत के आधार पर, 1996 की एफआईआर संख्या 240 (एक्स.पी-30) धारा 395, 396, 397 और 398 आईपीसी के तहत दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। गोपाल नेपाली और अनीता यादव के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. कुनिया - आरोपी/प्रतिवादी को 24/12/1996 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 29/12/1996 को एक प्रकटीकरण विवरण (एक्स.पी-76) दिया जिसके आधार पर रिकवरी मेमो (एक्स.पी-583) के माध्यम से एक चांदी का गिलास और एक हजार रुपये बरामद किए गए। इसके अलावा, उनके प्रकटीकरण बयान पर, 2/1/1997 को रिकवरी मेमो (एक्स.पी-52) के माध्यम से एक स्कूटर नंबर आरजे-05-0678 बरामद किया गया था।

"सी एक अन्य आरोपी तालेवर - प्रतिवादी, को 19/1/1997 को गिरफ्तार किया गया था और 26/1/1997 को दिए गए उसके प्रकटीकरण बयान पर, दो हजार रुपये, एक चांदी की अंगूठी और एम्बेसडर कार की एक चाबी जब्ती ज़ापन के माध्यम से बरामद की गई थी (पूर्व) .पी-45).

डी अन्य आरोपी व्यक्तियों से कुछ और बरामदगी की गई। जांच पूरी करने के बाद दोनों प्रतिवादियों सहित 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। चूंकि उन सभी ने खुद को निर्दोष बताया, इसलिए उन पर आईपीसी की धारा 395, 396 और 398 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

ई सत्र परीक्षण में अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 34 गवाहों की जांच की। आभूषणों और चोरी गए सामानों की पहचान शशि देवी (पीडब्लू 12) और संतोष जगवेयन (पीडब्लू 13) द्वारा की गई। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 2.11.2002 के फैसले और आदेश के तहत दो उत्तरदाताओं सहित 8 आरोपियों को दोषी ठहराया। राम कृष्ण नामक एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। उन सभी को आईपीसी की धारा 395, 396 और 397 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न

करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इन सभी को आईपीसी की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सात साल के कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। उन्हें आईपीसी की धारा 395 के तहत दोषी ठहराया गया, आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। अभियुक्त घूरेलाल, चुंचू उर्फ भगवान सिंह, कल्लू, राजपाल और समय सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 3/27 के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर उनमें से प्रत्येक को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एफ उक्त निर्णय से व्यथित होकर, दोनों उत्तरदाताओं सहित सभी आरोपियों ने 2002 की आपराधिक अपील संख्या 1579 को प्राथमिकता दी, जिसे उच्च न्यायालय ने निर्णय और आदेश दिनांक 27/10/2004 के माध्यम से दोनों उत्तरदाताओं/अभियुक्तों को बरी कर दिया है, हालांकि अन्य आरोपियों के संबंध में दोषसिद्धि और सजा। इसलिए, राज्य द्वारा उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ यह अपील की गई है।

3. राजस्थान राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने प्रस्तुत किया है कि लूटी गई कुछ संपत्ति की वसूली उक्त उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर की गई थी। कानून इस धारणा का प्रावधान करता है कि उन्होंने अपराध में भाग लिया था और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उक्त आरोपियों को गलत तरीके से बरी कर दिया है और इस प्रकार, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

4. इसके विपरीत, उक्त दोनों आरोपियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अल्ताफ हुसैन ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों के प्रकटीकरण बयान पर केवल लूटी गई संपत्ति की बरामदगी, आरोपों को वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लूट या डकैती का अपराध, जब वसूली घटना की तारीख से काफी अवधि की समाप्ति के बाद की जाती है और विशेष रूप से जब लूटी

गई संपत्ति की प्रकृति ऐसी होती है जिसे आसानी से बदला जा सकता है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया बरी करने का आदेश तथ्यों की उचित समझ और कानून के अनुप्रयोग पर पारित किया गया है। अपील में योग्यता नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. जहां तक दोनों उत्तरदाताओं/अभियुक्तों का संबंध है, स्वीकृत तथ्य यह है कि कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित ही नहीं की गई थी। इसके अलावा किसी भी चश्मदीद गवाह, विशेष रूप से शशि देवी (पीडब्लू 12), संतोष जगवेयन (पीडब्लू 13), कृपा दयाल यादव (पीडब्लू 2), प्रीति (पीडब्लू 14) और संध्या (पीडब्लू 15) ने उक्त उत्तरदाताओं में से किसी की भी पहचान नहीं की। कोर्ट। इसलिए, जहां तक उनकी पहचान का सवाल है, कोई सबूत नहीं है।

7. इस प्रकार, एकमात्र प्रश्न यह तय किया जाना बाकी है कि क्या आरोपियों के खिलाफ केवल उनके प्रकटीकरण बयानों पर की गई वसूली के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

7.1. गुलाब चंद बनाम एमपी राज्य, एआईआर 1995 एससी 1598 में, इस न्यायालय ने डकैती और हत्या के तुरंत बाद आरोपी व्यक्ति के कब्जे से मृतक के गहने की बरामदगी के आधार पर डकैती करने की सजा को बरकरार रखा।

7.2. गीजगंदा सोमैया बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2007 एससी 1355 में, इस न्यायालय ने गुलाब चंद (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि केवल चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चोरी की गई वस्तुएं किसी व्यक्ति के कब्जे में हैं। हत्या

और डकैती के अपराध का दोषी है. लेकिन उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी होना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पेश किए गए सबूतों की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

सांवत खान बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1956 एससी 54 में इस न्यायालय द्वारा यह संकेत दिया गया है कि कुछ परिस्थितियों से क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है।

7.3. तुलसीराम कानू बनाम राज्य, एआईआर 1954 एससी 1 में, इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114, चित्रण (ए) के तहत अनुमान लगाने की अनुमति महत्वपूर्ण समय कारक के तहत तैयार की जानी है। यदि हत्या के तुरंत बाद मृतक के पास मौजूद आभूषण किसी व्यक्ति के पास पाए जाते हैं, तो अपराध की धारणा की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यदि अंतराल में एक लंबी अवधि समाप्त हो गई है, तो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

7.4. इयरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1983 एससी 446 मामले में, इस न्यायालय ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ए) के तहत अनुमान की प्रकृति प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि कब्ज़ा हाल ही का है या अन्यथा। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। अपराध की धारणा को सही ठहराने के लिए हालिया कब्जे की मात्रा क्या है, यह सवाल अलग-अलग है, "चूंकि चोरी की गई वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में आसानी से जाने के लिए गणना की जाती है या नहीं"। यदि चोरी की गई वस्तुएँ ऐसी थीं जिनके आसानी से हाथ से जाने की संभावना नहीं थी, तो बीतने वाली एक वर्ष की अवधि को बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब अपीलकर्ता उस अवधि के दौरान फरार हो गया हो।

7.5. ऐसे ही एक तर्क के बाद संजय@काका ईएफसी में. ete. बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), एआईआर 2001 एससी 979, इस न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा क्योंकि अपराध के अगले दिन आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण बयान दिए गए थे और मृतक की संपत्ति बरामद की गई थी। उनके कहने पर उसी दिन उन स्थानों से जहां उन्होंने ऐसी संपत्तियां रखी थीं। अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित था कि घटना के अगले ही दिन आरोपी व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयान और उनके कहने पर उनसे भारी बरामदगी अपने आप में पर्याप्त परिस्थिति थी, जो स्पष्ट रूप से - यह दिखाने के लिए गई थी कि आरोपी डकैती के अपराध को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों ने हाथ मिलाया था। इसलिए, चोरी की संपत्तियों पर हाल ही में और अस्पष्ट कब्जे को भी हत्या के आरोप का अनुमानित सबूत माना जाएगा।

7.6. रॉनी एलियास रोनाल्ड जेम्स अलवारिस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1998 एससी 1251 में, इस न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं के कब्जे से मृतक के परिवार से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी जल्द ही डकैती और मृतक की हत्या को प्रभावित करती है। अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण अस्पष्ट रहा, और इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की व्याख्या (ए) के तहत अनुमान आकर्षित किया जाएगा:

> “यह निष्कर्ष निकालने के लिए किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि हत्या और सामान की लूट एक ही लेन-देन का हिस्सा पाई गई। इसलिए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होगा कि अपीलकर्ताओं और किसी और ने तीन हत्याएं और डकैती नहीं की थी।
>
> (यह भी देखें: बैजूर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1978 SC 522; और मुकुंद उर्फ कुंडू मिश्रा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1997 SC 2622)।

7.7. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि जहां अभियुक्तों के खिलाफ एकमात्र सबूत चोरी की संपत्तियों की बरामदगी है, तो हालांकि परिस्थितियां

यह संकेत दे सकती हैं कि चोरी और हत्या एक ही समय में की गई होगी, यह सुरक्षित नहीं है यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि चोरी की संपत्ति रखने वाले व्यक्ति ने हत्या की है। यह बरामद की गई संपत्ति की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि क्या इसके आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की संभावना है। संदेह को सबूत की जगह नहीं लेनी चाहिए.

8. वर्तमान मामले में, आरोपी कुनिया को 24/12/1996 को गिरफ्तार किया गया था और 29/12/1996 को उसके प्रकटीकरण बयान पर एक चांदी का गिलास और एक हजार रुपये बरामद किए जाने का आरोप लगाया गया था। पुनः प्रकटीकरण विवरण दिनांक 2/1/1997 पर, डकैती में इस्तेमाल किया गया कथित स्कूटर बरामद किया गया। इसी प्रकार, एक अन्य आरोपी तालेवर को 19/1/1997 को गिरफ्तार किया गया था और 26/1/1997 को उसके प्रकटीकरण बयान पर, दो हजार रुपये, एक चांदी की अंगूठी और अपराध में इस्तेमाल की गई एम्बेसडर कार की एक चाबी बरामद की गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं/अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी के प्रकटीकरण बयान पर वसूली घटना की तारीख से निकट समय में नहीं हुई थी। और तो और, वसूली या तो नकदी, छोटी चीज़ों या वाहनों की होती है जिन्हें बिना किसी कठिनाई के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, हम अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 चित्रण (ए) के तहत उक्त दोनों उत्तरदाताओं/अभियुक्तों के खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उनके प्रकटीकरण बयानों पर की गई बरामदगी के आधार पर उन्हें अपराध के कमीशन से जोड़ने के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

9. उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को बरी करने के फैसले और आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा तत्काल अपील तैयार की गई है। इस मुद्दे पर कानून इस आशय से अलग है कि केवल असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी परिस्थितियां हैं और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है। अपीलीय अदालत को अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट के बरी होने से उसकी बेगुनाही की धारणा को बल मिलता है। जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो वहां नियमित तरीके से हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

(देखें: ब्रह्म स्वरूप और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2011 SC 280; वी.एस. अच्युतानंदन बनाम आर बालकृष्ण पिल्लई और अन्य, (2011) 3 SCC 317; और रुकइया बेगम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 4 SCC 779)।

10. में. उपरोक्त को देखते हुए, हमें उक्त उत्तरदाताओं को बरी करने के उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अपील में योग्यता नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

आर पी अपील खारिज।

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।